राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक रिट याचिका संख्या 409/2024

1.महेंद्र कुमार शर्मा (सारस्वत) पुत्र रामेश्वर लाल शर्मा, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी 226, वार्ड नंबर 8, मलकीसर, कपूरीसर, तहसील लूणकरणसर, जिला। बीकानेर (पंचायत समिति सदस्य, वार्ड नंबर 14, लूणकरणसर) (राज.)।

2.सरस्वती पत्नी महेंद्र कुमार शर्मा (सारस्वत), उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 226, मलकीसर, कपूरीसर, तहसील लूणकरनसर, जिला। बीकानेर (सरपंच, ग्राम पंचायत पीपेरा, थाना लूणकरणसर) (राज.)।

3.महावीर प्रसाद पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी मकान नंबर 196, वार्ड नंबर 3, गांव बड़ेरन, पोस्ट कंकरवाला, तहसील लूणकरनसर, जिला। बीकानेर (ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पीपेरा, थाना लूणकरणसर) (राज.)

---याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के माध्यम से।
2. मोती राम पुत्र गोपाल राम, निवासी चक 1 बी.एच.डी., पीपेरा, तहसील लूणकरनसर, जिला। बीकानेर (राजस्थान).

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री श्रीकांत वर्मा

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री विक्रम राजपुरोहित, पीपी

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

23/08/2024

1. याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के समक्ष दायर एक निजी शिकायत को स्वीकार किए जाने से व्यथित हैं, जिसे सीआरपीसी की धारा 154 के तहत शिकायत मामला संख्या 12/2023 (अनुलग्नक-3) के रूप में पंजीकृत किया गया था। वे एसीबी के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करने सहित बाद की कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग करते हैं।

2. मामले के तथ्य काफी अजीब हैं। यह दलील दी गई है कि 24.07.2022 को प्रतिवादी संख्या 2 ने पुलिस स्टेशन लूणकरणसर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता महेंद्र सारस्वत और सरपंच सरस्वती ने मनरेगा कार्य के लिए फर्जी राशि निकालकर अनियमितताएं की हैं। जब शिकायतकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो याचिकाकर्ताओं ने कथित तौर पर उसे धमकाया और जाति-आधारित गालियों का इस्तेमाल किया। आईपीसी की धारा 458, 323, 327, 384, 506, 504 और 34 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(आर) और 3(1)(एस) के तहत एफआईआर संख्या 245/2022 दर्ज की गई और जांच की गई, जो 31.10.2023 को समाप्त हुई, जिसमें याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अंतिम नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई।

2.1. इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता ने लोकपाल, मनरेगा, जिला परिषद, बीकानेर को भी शिकायत प्रस्तुत की, जिस पर 20.10.2022 को निर्णय लिया गया। यह पाया गया कि जब अधिकारी शिकायतकर्ता की भूमि पर उचित निर्माण की सुविधा प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे, तो वह असहयोग कर रहा था। साक्ष्यों से पता चलता है कि शिकायतकर्ता एक ही आरोपों के आधार पर बार-बार शिकायत करके याचिकाकर्ताओं को झूठा फंसाने का प्रयास कर रहा है, खासकर नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के बाद।

2.2. प्रासंगिक रूप से, शिकायतकर्ता ने पहले की एफआईआर में नकारात्मक जांच रिपोर्ट के खिलाफ विरोध दर्ज नहीं किया, बल्कि उसी आरोपों के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में धारा 154(1) सीआरपीसी के तहत एक नई शिकायत दर्ज की। इसे शिकायत संख्या 12/2023 के रूप में दर्ज किया गया। एसीबी ने 21.08.2023 को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से दस्तावेज मांगे।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं और विद्वान लोक अभियोजक के विद्वान वकील को सुना है, और मैंने मामले की फाइल का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विचाराधीन शिकायत असमर्थनीय है तथा इसे निरस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि एफआईआर संख्या 245/2022 में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर नहीं की। इसके बजाय, उसने उन्हीं आरोपों के आधार पर एसीबी में धारा 154(1) सीआरपीसी के तहत एक नई शिकायत दर्ज करने का विकल्प चुना। इससे पता चलता है कि जब शिकायतकर्ता, प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मामले में झूठा फंसाने में विफल रहा, तो उसने एसीबी में शिकायत दर्ज करने का सहारा लिया।

4.1. इसके अलावा, शिकायतकर्ता ने लोकपाल, मनरेगा, जिला परिषद, बीकानेर को भी एक शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसका 20.10.2022 को समाधान किया गया। यह नोट किया गया कि जब अधिकारी शिकायतकर्ता के खेत पर उचित निर्माण की सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, तो उसने सहयोग करने से इनकार कर दिया। बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, उसने अपना अंगूठा नहीं लगाया और फोरेंसिक विश्लेषण पर जोर दिया, जो संभव नहीं था। इससे पता चलता है कि शिकायत राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और व्यक्तिगत प्रतिशोध से प्रेरित है। इसलिए, आरोपित शिकायत टिकने लायक नहीं है और सभी संबंधित कार्यवाही रद्द कर दी जानी चाहिए, उन्होंने तर्क दिया।

5. सबसे पहले, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि मैं याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के उपरोक्त तर्कों से सहमत हूं। कारण जानने के लिए बहुत दूर नहीं है। आइए देखें कि कैसे।

6. शिकायतकर्ता की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। एफआईआर संख्या 245/2022 में नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के बावजूद, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुआ, शिकायतकर्ता ने विरोध याचिका दायर नहीं करने का विकल्प चुना, जो उचित कानूनी उपाय था। इसके बजाय, उन्हीं आरोपों पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के साथ धारा 154 (1) सीआरपीसी के तहत एक नई शिकायत दर्ज करके, शिकायतकर्ता अनिवार्य रूप से पहले से ही बंद मामले को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। यह बिना किसी नए सबूत या आधार के मुद्दे को फिर से खोलकर याचिकाकर्ताओं को परेशान करने का एक स्पष्ट प्रयास है।

7. पुलिस जांच और लोकपाल में विफल होने के बाद एसीबी के समक्ष शिकायतकर्ता की नई शिकायत फोरम शॉपिंग के बराबर है। यह व्यवहार

कानूनी अंतिमता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और दोहरे खतरे के बराबर है। कानून किसी व्यक्ति को एक ही तथ्य और आरोपों पर अलग-अलग अधिकारियों के समक्ष लगातार शिकायतें दर्ज करने की अनुमति नहीं दे सकता, खासकर जब पूरी तरह से जांच की जा चुकी हो और मामले का निष्कर्ष नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के साथ निकाला गया हो। उन्हीं तथ्यों के आधार पर यह दूसरी शिकायत तुच्छ और दुर्भावनापूर्ण है।

8. यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने पुलिस जांच (एफआईआर संख्या 245/2022) की नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ विरोध दर्ज नहीं किया, यह दर्शाता है कि शिकायतकर्ता जांच के निष्कर्षों को कानूनी चुनौती देने में दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके बजाय, उसने पहले की जांच के निर्णायक परिणाम को दरकिनार करने के लिए एसीबी के पास एक नई शिकायत दर्ज करके पिछले दरवाजे से रास्ता अपनाया। यह रणनीति दर्शाती है कि शिकायतकर्ता का इरादा न्याय पाने का नहीं बल्कि याचिकाकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाने का है।

9. एसीबी के समक्ष शिकायत में कोई नई सामग्री या सबूत पेश नहीं किया गया है जो जांच को फिर से खोलने का औचित्य साबित करे। एफआईआर और लोकपाल के समक्ष तथा अब एसीबी की शिकायत में लगाए गए आरोप एक जैसे हैं। कोई नया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर एसीबी द्वारा जांच की आवश्यकता हो। इस प्रकार, धारा 154(1) सीआरपीसी के तहत नई शिकायत दर्ज करना निराधार है, क्योंकि मामले की पहले ही गहन जांच हो चुकी है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायत राजनीति से प्रेरित है और व्यक्तिगत प्रतिशोध से उपजी है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि शिकायतकर्ता अपने क्षेत्र में निर्माण संबंधी मुद्दों को हल करने के प्रयासों के दौरान अधिकारियों के साथ

असहयोगी रहा है, जो आगे संकेत देता है कि शिकायतकर्ता के गुप्त उद्देश्य हैं। लोकपाल के निष्कर्षों से यह और पुष्ट होता है कि शिकायतकर्ता असहयोगी था। लोकपाल और पुलिस द्वारा स्पष्ट निष्कर्षों और समापन के बावजूद बार-बार शिकायत दर्ज करना, वैध शिकायतों के बजाय राजनीतिक या व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित उत्पीड़न का संकेत है।

11. सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत प्रतिशोध के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। इस मामले में, बिना किसी नए तथ्य के पुरानी शिकायत के आधार पर आगे की कार्यवाही की अनुमति देना केवल शिकायतकर्ता के निजी एजेंडे को पूरा करता है और जनहित को पूरा नहीं करता। ऐसी शिकायतों को सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए, खासकर जब जांच याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पहले ही समाप्त हो चुकी हो।

12. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। शिकायत मामला संख्या 12/2023 (अनुलग्नक-3), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर के समक्ष लंबित है, और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।